हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक : 281 : जौनपुर, गुरुवार 13 जुलाई 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य : 2 रूपया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज की संकल्पना को कर रहे साकार

एजेन्सी

लखनऊ। मिशन निरामया के तहत बुधवार को राजधानी के मुख्यमंत्री आवास में मऊ और शामली जिले में निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुबंध किया गया। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग भी की गई। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा है कि साल 2017 के पहले प्रदेश में मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और आज यूपी में 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा 16 निर्माणाधीन है। जिनमें 14 सरकारी और दो प्राइवेट हैं और आज दो और नए मेडिकल कॉलेज के लिए एमओयू हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये मेडिकल शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा गुणवत्तापूर्ण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि मिशन निरामया गत वर्ष में शुरू किया गया था और आज वह देश का ब्रांड बन गया है। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग और पैरामेडिकल बैक बोन होता है। साल 2017 से पहले मेडिकल शिक्षा की चर्चा तो की गई लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल को भूल गए। साथ ही कई जगह पर कॉलेज बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकेल्टी के काम कर रहे थे। हमने 6 साल के कार्यकाल में इसे बेहतर करने का काम किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी चिकित्सा संस्थान ने मानक पूरा करता है तो ही उसे संबद्धता और सुविधा दी जाए अगर वे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकेल्टी, लैब, लाइब्रेरी की सुविधा समेत अन्य मानक पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे संस्थानों को बाहर कर दिया जाएगा। हम प्रदेश के किसी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मेडिकल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी संस्थान देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले प्रदेश में मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज यूपी में 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। 16 अन्य में निर्माण चल रहा है। 14 सरकारी और दो प्राइवेट। आज दो नए मेडिकल कॉलेज के लिए एमओयू हुआ है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह न सिर्फ मेडिकल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य सुविधा गुणवत्तापूर्ण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे मिशन निरामया के तहत क्यूसीआई की ओर से नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग व मऊ व शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुबंध कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ और शामली में मेडिकल कॉलेज एक सपना था, जो अब साकार हो रहा है। यह वे जिले हैं, जहां पहले लोग जाने में डरते थे। मऊ माफिया के लिए जाना जाता था, शामली का भी यही हाल था। अब यहां क्वालिटी स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ क्वालिटी इलाज भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मिशन निरामया जो गत वर्ष शुरू किया गया था। आज देश का ब्रांड बना हुआ है। नर्सिंग और पैरामेडिकल बैक बोन होता है। मेडिकल शिक्षा की चर्चा तो की गई लेकिन नर्सिंग व पैरामेडिकल को भूल गए।

कुल्लू घाटी से सुरक्षित निकाले 2500 पर्यटक वाहनय चंद्रताल में फंसे टूरिस्ट, बचाव टीम रवाना

एजेन्सी

शिमला हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक हुई भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ के बाद सामान्य जनजीवन अभी भी अस्त–व्यस्त है। हालांकि बाढ़ और भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित कुल्लू जिले के कुछ हिस्सों में बीती रात बिजली आपूर्ति और मोबाइल फोन सेवाएं बहाल होने से लोगों, खासकर पर्यटकों को राहत मिली है। आज लाहौल स्पीति के चंद्रताल झील इलाके में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए जमीन व आसमान से जारी अभियान फिर से आरंभ हो गया है। इन पर्यटकों को निकालने के लिए स्पीति की ओर से जहां सड़क मार्ग से अभियान आरंभ किया गया है, वहीं वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रयासरत है। इस बीच, मौसम विभाग ने आज से राज्य में मानसून की वर्षा संबंधी गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई से प्रदेश में मानसून से जुड़ी गतिविधियों में फिर से तेजी आएगी। विभाग ने 15 जुलाई को प्रदेश में फिर से भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। एडीसी काजा राहुल जैन के अनुसार अभी तक 12 किलोमीटर रोड बहाल किया जा चुका है जबकि 25 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटानी शेष है। उन्होंने कहा कि कुंजुम दर्रे से होते हुए एक सन्देश वाहक पैदल टीम चंद्रताल टैंट कैम्प में पहुंच गई है। ये टीम चंद्रताल में फंसे पर्यटकों का हौसला बढ़ाने के लिए गई है ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रयासरत है। राहुल जैन ने कहा कि चंद्रताल में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि बीती रात कुल्लू–मनाली और आसपास के कुछ इलाकों के लिए सड़क संपर्क बहाल कर दिए जाने के बाद लगभग 2500 पर्यटक वाहन घाटी से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कसोल और पार्वती घाटी के लिए सड़क संपर्क बहाल करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं।राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों के लिए पेयजल आपूर्ति करने वाली योजनाओं के लगातार बंद रहने के चलते शहर में आज पांच दिन बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। शहर की भट्टाकुफर फल मंडी में बीती रात भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में फल मंडी की छत टूट गई। सोलन जिले में एक दिन की राहत के बाद आज फिर सुबह से भारी वर्षा हो रही है। जिले में बीते पांच दिनों के दौरान हुई भारी वर्षा से अभी भी 100 से अधिक सड़कें अवरूद्ध हैं। सोलन के साथ लगते शामती क्षेत्र में 10 घरों में दरारें आ जाने के चलते प्रशासन ने उन्हें बीती रात खाली करवा दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मणिकर्ण, बंजार और अन्य स्थानों पर अभी भी लगभग 7000 वाहन फंसे हुए हैं।

उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 24 जुलाई तक टाली

एजेन्सी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक टाल दिया। खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ 24 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई।दिल्ली पुलिस के वकील ने हजारों पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट का हवाला देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांग लिया। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने, वह व्यक्ति दो साल और ग्यारह महीने से हिरासत में है। अब क्या जवाब (शपथ पत्र) दाखिल करना है? यह जमानत याचिका है। खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को रेगुलर बेल की मांग वाली खालिद की अपील खारिज कर दी थी। खालिद ने ट्रायल कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। खालिद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अमरावती में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है जिसके चलते कथित रूप से दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जेएनयू स्कॉलर और कार्यकर्ता खालिद और शरजील इमाम राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों से जुड़े कथित बड़े साजिश मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में से हैं।

ऐपल का भारत से निर्यात बढ़ा, पहली तिमाही में 20 हजार करोड रुपए के पचीवदम का एक्सपोर्ट

एजेन्सी

नयी दिल्ली। ऐपल इंक ने भारत से आईफोन निर्यात में शानदार सफलता हासिल की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही में 20,000 करोड रुपए मूल्य के आईफोन का भारत से निर्यात किया, जो पूरे वित्त वर्ष 2023 में किए गए कुल निर्यात का करीब 50 प्रतिशत है। पहली तिमाही के आंकडों से पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही (सिर्फ 4,950 करोड रुपए का निर्यात) के मुकाबले आईफोन निर्यात में 400 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। उत्पादन केंद्रित रियायत योजना के तहत उसके तीन विक्रेताओं–फॉक्सकॉन हॉन हई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने वित्त वर्ष 2024 (योजना के तीसरे वर्ष) में 61,000 करोड रुपए के निर्यात की प्रतिबद्धता जताई है। अच्छी खबर यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के लिए इस निर्यात प्रतिबद्धता का एक–तिहाई निर्यात पहली तिमाही में ऐपल के विक्रेताओं द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष लक्ष्य बाकी तीन तिमाहियों में पूरा किया जाएगा। ऐपल के शानदार निर्यात प्रदर्शन के आधार पर विश्लेषकों का कहना है कि पीएलआई योजना के तहत निर्यात कंपनी की प्रतिबद्धता से ज्यादा रह सकता है। निर्यात में बडी तेजी आईफोन मॉडल 12, 13 और 14 की मदद से दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023 (जब सभी तीन विक्रेता वित्तीय रियायतों के लिए पात्र थे) के मोबाइल के लिए पीएलआई के दूसरे पूरे वर्ष में, उनका संयुक्त आईफोन निर्यात 40,000 करोड रुपए पर पहुंच गया। उस वित्त वर्ष में, ऐपल ने देश से किए गए 90,000 करोड रुपए मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात में 45 प्रतिशत योगदान दिया था। पिछले साल भारत से मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2022 के 45,000 करोड रुपए के मुकाबले करीब 100 प्रतिशत तक बढ गया। मोबाइल फोन निर्यातकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट को भी पिछले वित्त वर्ष शीर्ष–पांच निर्यात में से एक बनाए जाने में मदद की। इसके अलावा शीर्ष–5 निर्यात क्षेत्रों में चार इंजीनियरिंग वस्तु, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, जैविक एवं गैर–जैविक रसायन शामिल रहे। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक 50–58 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात का लक्ष्य रखा है, हालांकि इंडियन सेल्युलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का मानना है कि यह लक्ष्य संभव नहीं हो सकता है और तब तक सिर्फ 40–45 अरब डॉलर का निर्यात हो सकता है। यह अंतर चीन के ब्रांडों से निर्यात में आशाजनक तेजी नहीं आने की वजह से देखा जा सकता है। संगठन का अनुमान है कि चीनी ब्रांडों का निर्यात वित्त वर्ष 2026 तक 10–12 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में इसने संयुक्त रूप से महज 15.7 करोड डॉलर का आंकडा छुआ।

शीला दीक्षित के आवास पर शिफ्ट हो सकते हैं राहुल गांधी

एजेन्सी

नयी दिल्ली। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था। अब वो एक नए पते पर शिफ्ट होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की दिग्गज नेता शीला दीक्षित के आवास पर शिफ्ट हो सकते हैं। तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित के बेटे और पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने पहले ही राहुल गांधी के लिए मकान खाली कर दिया है। राहुल गांधी ने यह मकान किराये पर लिया है। सेंट्रल दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित अपना आधिकारिक आवास खाली करने के बाद, राहुल गांधी अप्रैल में अपनी मां और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में चले आए थे।

राहुल गांधी की आवाज दबाने का रिजल्ट है हिमाचल और कर्नाटक : रंधावा

एजेन्सी

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस के संगठन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी की आवाज दबाने का परिणाम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे में सामने आ गया और आगामी चुनावों में भी यही दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराना उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये बुधवार को यहां शहीद स्मारक पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय "मौन सत्याग्रह किया। इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे रंधावा ने संवाददाताओं से कहा, ''ये (केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा) राहुल गांधी का संसद में तो बोलना बंद कर सकते हैं पर उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और हिंदुस्तान के लोग कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रंधावा ने आगे कहा, ''आपने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक (विधानसभा चुनाव) में, राहुल की आवाज दबाने का परिणाम उन लोगों ने दे दिया। और जो आगे चुनाव आ रहे हैं वहां भी वही परिणाम मिलेगा जो इन दोनों राज्यों में मिला। संसद में भी हम जीत कर आएंगे। उन्होंने कहा, ''भाजपा हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हमारी आवाज कभी नहीं दबेगी और देश के लिए हमेशा उठती रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी की निडर एवं समझौता विहीन राजनीति के समर्थन में उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को सुबह दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय ''मौन सत्याग्रह आयोजित किया है।

मुंबई रात के समय अब महिला कोचों और प्लेटफार्मों पर वर्दीधारी कर्मियों को किया जाएगा तैनात

एजेन्सी

मुंबई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपनगरीय ट्रेन के महिला डिब्बों और प्लेटफॉर्म पर रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच वर्दीधारी कर्मियों को तैनात करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह कदम मुंबई में उपनगरीय ट्रेन में महिला यात्रियों के यौन उत्पीडन की हालिया घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है। पिछले महीने शहर में चलती ट्रेन में महिलाओं के यौन उत्पीडन और उन्हें प्रताडति करने की दो घटनाएं सामने आईं। रेलवे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों मामले सुलझा लिये। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जीआरपी ने ट्रेन यात्रा के दौरान खासकर रात और सुबह के समय महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच महिला डिब्बों में वर्दीधारी कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इन कर्मियों को जीआरपी, होम गार्ड और महाराष्ट्र सुरक्षा बल से लिया जाएगा तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारी भी जीआरपी के साथ समन्वय में काम करेंगे।

मुंबई उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क मध्य, पश्चिमी, हार्बर, ट्रांस–हार्बर और बेलापुर–नेरुल–खारकोपर (उलवे) लाइन में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि रात के समय रेलवे इन मार्गों पर 1,041 ट्रेन का संचालन करता है। अधिकारी ने बताया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जीआरपी ने ट्रेन में 640 और प्लेटफॉर्म पर 600 से अधिक कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है।

मोदी उपनाम टिप्पणी, बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी मानहानि मामले में दाखिल की कैविएट

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले के शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पूर्णेश मोदी ने उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दाखिल की है। कैविएट में अनुरोध किया गया है कि अगर राहुल गांधी मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कोई याचिका दाखिल करते हैं, तो शिकायतकर्ता के पक्ष को भी सुना जाए। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सात जुलाई को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक पूर्णेश मोदी ने वकील पी एस सुधीर के माध्यम से उसी दिन उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की। कैविएट किसी वादी के द्वारा अपीलीय अदालत में दाखिल की जाती है और उसमें निचली अदालत के फैसले अथवा आदेश को चुनौती देने वाली विपक्षी की याचिका पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले उसके पक्ष के सुने जाने का अनुरोध किया जाता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनामश को लेकर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक संबंधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ''राजनीति में शुचिता समय की मांग है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने 53 वर्षीय गांधी की याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, ''जनप्रतिनिधियों को स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना नियम नहीं, बल्कि अपवाद है, जो विरले मामलों में इस्तेमाल होता है। इसने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। गांधी की सजा पर अगर रोक लग जाती तो लोकसभा सदस्य के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता। फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी। इसने आरोप लगाया कि सरकार गांधी की आवाज को दबाने के लिए ष्नई तकनीकष ढूंढ़ रही है क्योंकि वह उनके सच बोलने से परेशान है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा 2019 में दायर एक मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मामला गांधी की इस टिप्पणी से संबंधित था कि ''सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी क्यों होता है। यह टिप्पणी कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को की गई थी।

दिल्लीः यमुना के जलस्तर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 207.55 मीटर तक पहुंचा लेवल...धारा 144 लागू

एजेन्सी

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़–संभावित क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर तक बढ़ गया। इससे पहले 1978 में यमुना नदी का जलस्तर यहां रिकॉर्ड 207.49 मीटर तक पहुंचा था। सीआरपीसी की धारा 144 चार या उससे अधिक व्यक्तियों के गैर–कानूनी जमावड़े और समूहों में सार्वजनिक आवाजाही को प्रतिबंधित करती है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक परामर्श जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है और निचले इलाकों में आवाजाही न करने की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि चूंकि यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसलिए लोगों को बिजली लाइन से दूर रहना चाहिए और किसी भी जरूरत की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर– 1077 पर संपर्क करना चाहिए। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी बाढ़ की स्थिति और निवारक उपायों का जायजा लेने के लिए राहत शिविरों का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नदी के तटबंधों को मजबूत कर रही है और लोगों को बाढ़–प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाल रही है। अधिकारियों के मुताबिक, वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के पास गढ़ी मांडू गांव जलमग्न हो गया है।

महंगा हुआ सोना–चांदी के वायदा भाव 71 हजार रुपए से ऊपर

एजेन्सी

नयी दिल्ली। सोने–चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। दोनों के वायदा भाव बुधवार को तेजी के साथ खुले। चांदी के वायदा भाव 71 हजार रुपए से ऊपर कारोबार कर रहे हैं, सोने के वायदा भाव बढकर 59 हजार के करीब पहुंच गए हैं। सोने–चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। सोने के भाव लगातार 58 हजार रुपए के करीब बने थे। आज इनमें उछाल आया है। पिछले कई दिनों से सोने के दाम लुढक रहे थे। आज चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है। हालांकि कल भी चांदी में तेजी देखी गई थी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार की सुबह 4 अगस्त 2023 को डिलीवरी वाला सोना बढत के साथ 58900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। यह मंगलवार की शाम को 58773 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। वहीं 5 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी वाला सोना उछाल के साथ 59250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। यह बीते मंगलवार की शाम को 59110 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने में तेजी के बीच चांदी के भाव भी बढ गए हैं। चांदी की कीमतों में बुधवार की सुबह तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर बुधवार की सुबह 5 सितंबर 2023 को डिलीवरी वाली चांदी का भाव 71421 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर खुला है। सोने की वैश्विक कीमतों में बुधवार की सुबह तेजी देखी जा रही है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में दो प्रतिशत बढी सियाम

एजेन्सी / नयी दिल्ली। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर दो प्रतिशत बढकर 3,27,497 इकाई हो गई। उद्योग निकाय सियाम ने बुधवार को यह जानकारी दी। आंकडों के मुताबिक जून 2022 में डीलरों को 3,20,985 यात्री वाहन भेजे गए थे। सियाम ने कहा कि पिछले महीने दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री दो प्रतिशत बढघ्कर 13,30,826 इकाई हो गई।

सम्पादकीय

नियुक्ति को नकारा

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाये जाने को अवैध बताते हुए सरकार से उन्हें 31 जुलाई तक हटाने को कहा है। हालांकि, तीसरी बार बढ़ाया गया उनका कार्यकाल अभी 18 नवंबर तक था। कोर्ट ने सरकार से इस पद पर बीस दिन में नयी नियुक्ति करने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि मिश्रा का तीसरा कार्यकाल बढ़ाया जाना अवैध है। दरअसल, कोर्ट पहले भी सरकार को कह चुकी थी कि संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार न बढ़ाया जाये। सरकार की दलील थी कि वे अभी मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी कर रहे हैं। जिसकी वजह से नई नियुक्ति के लिये सरकार कुछ समय चाहती है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह फैसला कॉमन कॉज नामक स्वयंसेवी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गत आठ मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। दरअसल, वर्ष 2021 में जब कोर्ट ने निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने से मना किया था तो इसके खिलाफ केंद्र सरकार 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिये एक अध्यादेश लायी थी। इस संशोधन में प्रावधान रखा गया कि देश की महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। तदुपरांत केंद्र ने तीसरी बार संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया। हालांकि, कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने वाले कानून में बदलाव को वैध माना, लेकिन नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट का मानना था कि किसी भी जांच एजेंसी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जाना तार्किक होना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस ने भी याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने–धमकाने और राजनीतिक लाभ के लिये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है। पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रवर्तन निदेशालय की ही रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं व कारोबारियों के लेनदेन में कथित अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही थी। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं। यही वजह है कि संजय मिश्रा के मामले में याचिका दायर करने वालों की दलील थी कि ईडी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और देश हित में उसे स्वतंत्र होना चाहिए। कोर्ट ने भी सवाल किया था कि क्या वजह है कि उसके आदेश के बावजूद मिश्रा का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं सरकार की दलील थी कि मिश्रा कई संवेदनशील व महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे हैं, जिसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाना बाकी है। केंद्र के पक्षकार का तर्क था ईडी डायरेक्टर संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कई अहम मामलों की जांच देख रहे हैं। वे फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की समीक्षा में शामिल हैं जिसको लेकर अभी काफी काम किया जाना बाकी है। अतरू उनका देश हित में पद पर बने रहना जरूरी है। साथ ही यह भी कि योग्य अफसर तलाशने में अभी वक्त लगेगा। उल्लेखनीय है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 1984 बैच के अधिकारी संजय मिश्रा 34 साल तक विभाग को सेवा दे चुके हैं। साथ ही विदेशों में धन छुपाने वाले भारतीयों के मामलों में निगरानी करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सेवाएं दे चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस, यस बैंक, आईसीआईसीआई सीईओ चंदा कोचर प्रकरण की जांच की उन्होंने निगरानी की है। वहीं जानकारों का मानना है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बार–बार बढ़ाए जाने से क्षुब्ध विभाग के उन अधिकारियों ने भी उनके खिलाफ मोर्चाबंदी आरंभ कर दी जो देश की महत्वपूर्ण एजेंसी के निदेशक बनने के दावेदार थे। बहरहाल, इस मामले में केंद्र सरकार की किरकिरी तो हुई है जिसे विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को झटका

ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलाजी ने भारत के वेदांता समूह के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर उत्पादन प्लांट लगाने को 19.5 अरब डॉलर का निवेश समझौता रद्द कर दिया है। दोनों औद्योगिक समूहों के बीच पिछले साल ही गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता किया था। इसे सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा करार माना गया था। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कंपनियों में से एक है। एपल का चर्चित आईफोन भी यह कंपनी बनाती है। पिछले कुछ सालों में फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर निर्माण में भी कदम बढ़ाए हैं। डिजिटल हो चुकी दुनिया में सेमीकंडक्टर के बिना किसी का काम नहीं चल सकता है। सेमीकंडक्टर आम तौर पर सिलिकॉन चिप होते हैं, जो कंप्यूटर, मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन से लेकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामानों और वाहनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रकृति में कुछ पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ कुचालक। अर्थात कुछ पदार्थ विद्युत तरंगों को अपने भीतर से गुजरने देते हैं वो सुचालक होते हैं और कुछ इन तरंगों को रोक लेते हैं वो कुचालक होते हैं। इनके बीच होते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, इन में विद्युत प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से अधिक और सुचालक से कम होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, गैलियम कुछ प्रमुख अर्धचालक हैं, इनमें से सिलिकॉन का इस्तेमाल

सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। दुनिया में ताइवान, चीन और जापान जैसे चुनिंदा देशों में ही सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होता है। पिछले साल जब भारत में इसके निर्माण को लेकर करार हुआ तो इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच टूटे करार को मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साढ़े 19 अरब डॉलर का यह समझौता क्यों टूटा, इसका कोई स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। फॉक्सकॉन ने कहा कि उसने सेमीकंडक्टर के एक महान विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए वेदांता के साथ एक साल से अधिक समय तक काम किया था। लेकिन अब इस संयुक्त उपक्रम से बाहर निकलने का फैसला लिया गया है। कंपनी ने कहा कि यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हुआ है। अब यह पूरी तरह से वेदांता के स्वामित्व वाली इकाई होगी। वेदांता समूह धातु से तेल तक का कारोबार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर बनाने का कोई अनुभव उसके पास नहीं है। ऐसे में यह देखना होगा कि अब गुजरात में शुरु हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्या हश्र होगा। इस समझौते का रद्द होना भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है। क्योंकि अब चिप निर्माण के लिए विदेशी निवेशकों को लुभाने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। इसके अलावा रोजगार के पक्ष पर भी भारत नुकसान में पड़ गया है। पिछले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐन पहले वेदांता लिमिटेड ने फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की थी। गांधीनगर में एक समारोह में रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संयंत्र के लिए गुजरात सरकार द्वारा पूंजी खर्च और सस्ती बिजली पर वित्तीय और गैर वित्तीय सब्सिडी देने की घोषणा भी हो गई थी। सरकार ने दावा किया कि इससे एक लाख के लगभग रोजगार पैदा होंगे। निश्चित ही इस समझौते का लाभ भाजपा को गुजरात चुनाव में हुआ। खास बात ये है कि ये संयंत्र पहले महाराष्ट्र में लगना तय हुआ था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने इसकी सारी तैयारी कर ली थी और तालेगांव में संयंत्र स्थापना की संभावनाएं तलाशनी शुरु हो गई थीं। इस बीच महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। उद्धव ठाकरे की जगह शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। जुलाई 2022 में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, लेकिन अचानक से यह परियोजना गुजरात में लगाने का फैसला लिया गया। महाविकास अघाड़ी ने इस पर शिंदे सरकार पर सवाल उठाए कि महाराष्ट्र को मिलने वाला यह संयंत्र गुजरात कैसे चला गया। क्या उद्योगपतियों को महाराष्ट्र की नयी सरकार पर भरोसा नहीं रहा या फिर प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में शिंदे सरकार ने अपना हक छोड़ दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सवालों का कोई जवाब शिंदे सरकार से नहीं मिला। परियोजना गुजरात चली गई और अब साल भर बाद गुजरात को भी खाली हाथ रह जाना पड़ा है। फॉक्सकॉन–वेदांता के बीच समझौता रद्द होने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में साल दर साल होते रहे ऐसे समझौतों का यही अंजाम होता है। इसी की नकल में यूपी में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर समिट का भी यही अंजाम होगा। चाहे गुजरात मॉडल की बात हो या न्यू इंडिया की, कभी भी प्रायोजित हेडलाइन पर विश्वास ना किया जाए। कांग्रेस के इस वार पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा कि कांग्रेस ने तीन दशकों तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकॉन के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के इस पर हाय तौबा मचाने से भारत की प्रगति धीमी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार का काम नहीं है कि वो देखे कि क्यों दो निजी कंपनियां कैसे और क्यों साथ आती हैं या अलग हो जाती हैं। यह सही है कि दो निजी कंपनियों के बीच होने वाले व्यापारिक समझौतों में सरकार का कोई लेना–देना नहीं होता है, लेकिन क्या भारत में वाकई ऐसी स्थिति है। अगर ये केवल फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच की बात थी, तो फिर उनके एमओयू हस्ताक्षर पर केन्द्रीय मंत्री क्यों मौजूद थे और क्यों चुनाव के पहले परियोजना एक राज्य से दूसरे राज्य चली गई। जाहिर है, इस समझौते में कहीं न कहीं राजनैतिक खेल भी चल रहा था, शायद इसी का खामियाजा अब देखने मिला है। हालांकि वेदांता का दावा है कि वह भारत की पहली सेमीकंडक्टर उत्पादन ईकाई को स्थापित करने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ वार्ता कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि गुजरात में मिले इस झटके का राजनैतिक असर देश में किस तरह पड़ता है।

हिमाचल: प्रकृति का प्रतिशोध

मॉनसून की भारी वर्षा ने यूं तो उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक काफी नुक्सान पहुंचाया है लेकिन सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रभावित हुआ है। जल प्रलय से हिमाचल के पुल, सड़कें, मकान एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे हैं और पहाड़ों से आ रहा मलबा हिमाचल की जो तस्वीर बना रहा है उससे राज्य के लोगों का दर्द काफी बढ़ चुका है। राज्य का विकास थरथर कांप रहा है। लगातार हो रही मौतों से चारों तरफ क्रंदन ही क्रंदन सुनाई देता है। दरक रहे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि अब प्रकृति के कहर को मापना मुश्किल हो चुका है। कुछ दिन पहले तक हिमाचल में पर्यटकों की भीड़ थी लेकिन राज्य में बाढ़, बादल फटने, जल धाराओं में उफान और भूस्खलन में मौतों की खबरों के बाद पर्यटकों ने दूरी बना ली है और फंसे हुए पर्यटक किसी न किसी तरह वापिस लौट रहे हैं। प्रकृति के कहर ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए कुदरत के रौद्र के सामने उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी के बाद भी मनुष्य ने कुछ नहीं सीखा। सब जानते हैं कि मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति पर जो कहर ढाया था उसी का प्रतिशोध प्रकृति ले रही है। हिमाचल की पूर्व की सरकारों ने विकास के नाम पर जो कुछ भी किया उसी के चलते ही हिमाचल के खौफनाक दृश्य सामने आए। अब हालात ऐसे हैं कि जो विज्ञान राज्य के लोगों को वरदान लगता था, आज वही श्राप लगने लगा है। हिमाचल के भौगोलिक परिदृश्य पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदर अनुभूति हमारे मन–मस्तिष्क को पुलकित कर देती है। हिमाचल का जब कहीं कोई जिक्र चलता है तो इसकी प्राकृतिक भौगोलिक सुंदरता का दृश्य सहज ही हमारे जहन में आ जाता है। गौरव के साथ खड़े पहाड़, निरंतर जीवन प्रवाह के साथ बहती नदियां, हरितिमा से ओत–प्रोत वन इस पहाड़ी प्रदेश को एक अलग पहचान देते हैं। वर्तमान में इंसान ने औद्योगिकीकरण और भीड़भाड़ से हटकर शांत स्थानों पर आशियाने की तलाश में पहाड़ों व वनों से छेड़छाड़ को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में पहाड़ियों को काटना व कुरेदना निरंतर जारी है। प्रतिबंध होने के बावजूद अवैध व अवैज्ञानिक खनन चोरी–छिपे और कहीं–कहीं तो सरेआम जारी है। घने जंगलों तक भी आज के

मशीनीकरण ने अपनी पहुंच बना ली है। इसके परिणामस्वरूप पहाड़ियों को समतल बनाने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। गड्ढों, नालों व प्राकृतिक प्रवाहों से छेड़छाड़ व उन्हें अवरुद्ध करने का खामियाजा व्यक्ति को बरसात के दिनों में सामान्यतः हर वर्ष ही भुगतना पड़ता है। जब प्रकृति प्रवाहों की बाधाओं को हटाने के लिए संघर्ष करती है तो वह इसके कई भयावह निशान मानवीय बस्तियों की क्षति के रूप में छोड़ जाती है। उन हालात में हमें प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण व व्यवहार को बदलने की अकल आती है। दुख यह कि यह विवेक भी कुछ वक्त के लिए ही रहता है और थोड़े ही वक्त में हम सब कुछ भुलाकर उसी पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं जहां से सीधे–सीधे प्रकृति के प्रभुत्व को चुनौती मिलती है। हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर, नदियों और नालों पर घ्होटल बना दिए गए। लोगों ने नदियों को नजरअंदाज कर अपनी जमीन से कहीं आगे बढ़कर नदियों के किनारे मकान बना लिए। लोगों ने सोचा कि नदियां अब उनसे काफी दूर हो गईं हैं। जबकि नदियां अपना रास्ता कभी नहीं भूलतीं। जब भी बाढ़ आएगी तो नदियां अपना रास्ता खोज लेती हैं। पुराने जमाने में घर और बस्तियां नदियों से बहुत दूर थीं। नदियों को अविरल बहने दिया जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 12 हजार ऐसी छोटी नदियां हैं जिनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो चुका है। लगभग 6000 नदियां हिमालय से उतर कर आती थीं। अब उनमें से महज 500 का ही अस्तित्व बचा है। नदियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। हिमाचल में अब तक 4000 करोड़ का नुक्सान हो चुका है। राज्य की सड़कों, बिजली के ट्रांसफार्मरों, विद्युत उपकेन्द्रों और जल आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुक्सान पहुंचा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केन्द्र से हिमाचल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और हर सम्भव मदद का आग्रह धकिया है। राज्य सरकार इस विकट स्थिति से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है लेकिन जितना नुक्सान हो चुका है उसके पुनर्निर्माण और स्थिति सामान्य होने में काफी समय लग जाएगा। मंडी, धर्मशाला, चम्बा, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल में स्थितियां बहुत विकट हो चुकी हैं। भारी वर्षा से नुक्सान तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी हुआ है। राज्य सरकारों कोधइस आपदा से सबक सीखना चाहिए और उन्हें अंधाधुंध शहरीकरण की बजाय हिमालय परिस्थिति को ध्यान में रखकर विकास का मॉडल अपनाना चाहिए। हिमाचल में जहां भी सड़क बनी वहीं बाजार बन गया और जहां बाजार बना वहीं सड़क बन गई।

अब तो ऊना में भी डूबने के मंजर दिखाई दे रहे हैं और चम्बा की वादियां भी डूब रही हैं। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घविकास का खामियाजा इंसान भुगत रहा है। केवल पर्यावरण की योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। पहाड़ी राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त विकास की जरूरत है ताकि नवसृजन किया जा सके। प्रकृति के प्रभुत्व से कौन टकरा सकता है। राज्य सरकारों को प्रकृति के साथघ्तालमेल स्थापित कर आगे बढ़ना होगा ताकि भविष्य में आपदाओं से बचा जा सके।

मणिपुर हिंसा का मानवीय पक्ष

आदित्य नारायण

मणिपुर की अन्तर्जनजातीय हिंसा को लेकर निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों में बेचैनी का माहौल है और यह जानने की उत्सुकता भी है कि आखिरकार इसका मूल कारण क्या है? यह सत्य है कि अधिसंख्य उत्तर

व दक्षिण के लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों की सामाजिक–आर्थिक व राजनैतिक संरचना के बारे में गहरे से जानकारी नहीं होती है। इसमें भी अगर हम हिन्दी क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करें तो उन्हें सबसे कम जानकारी रहती है। इसके कई कारण हैं जिनमें एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि हिन्दी पत्रकारिता पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उदासीन रही है लेकिन अब समय बदल चुका है और इंटरनेट का जमाना है अतः आज की युवा पीढ़ी पुरानी वर्जनाओं को तोड़ कर जब चाहे आगे निकल सकती है। मणिपुर की हिंसा पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गहरी चिन्ता जताई थी और विगत 3 जुलाई को आदेश देकर राज्य सरकार से पूछा था कि वह तब तक की राज्य की परिस्थितियों के बारे में उसे अवगत कराये। अतः राज्य सरकार ने सिलसिलेवार कल न्यायालय में ब्यौरा रखते हुए बताया कि विगत 4 जुलाई तक राज्य में हिंसा के चलते कुल 142 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 54 हजार से ज्यादा नागरिक बेघर–बार होकर राहत शिविरों में शरण लिये हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसा व आगजनी की घटनाएं राजधानी इम्फाल के इर्दघ्–गिर्द इलाकों में ही हुई हैं उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के चन्द्रचूड़पुर जिले में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। साथ ही घाटी के विष्णुपुर व काकचिंग में हिंसा की बड़ी घटनाएं देखने में आयीं। राज्य सरकार ने इस हिंसा पर काबू पाने के लिए सभी संभव प्रयास किये हैं और अब इसमें कमी आ रही है। राज्य सरकार मैतेई व कुकी जनजातियों द्वारा बनाये गये बंकरों को भी नष्ट करने का अभियान चला रही है जिससे लोग अपने–अपने काम–धंधे के बारे में सोच सकें और खेती–किसानी की तरफ बढ़ सकें। राज्य में फिलहाल धान की बुवाई का काम चल रहा है। जाहिर है कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय को यह समझाना चाहा कि वह अपने नियन्त्रण में सारी सरकारी मशीनरी और अधिकारों का प्रयोग करके हिंसा पर काबू पाने के प्रयासों में लगी हुई है। मगर दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि राज्य की चुनी हुई एन. बीरेन सिंह सरकार की नाक के नीचे दो जनजातियों के बीच वैमनस्य का इतना जबर्दस्त माहौल क्या रातों–रात ही बन गया? कुकी और मैतेई जनजातियों के समुदायों में एक–दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल बनाने में क्या कोई राजनीति भी रही है? ये सब एक प्रश्न हैं जिनके बारे में सवाल उठने लाजिमी हैं परन्तु सर्वोच्च न्यायालय का इनमें कोई दखल नहीं हो सकता। शायद यही वजह रही कि कल मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने दोनों ही पक्षों के वकीलों से साफ–साफ कहा कि वे यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि हम इस न्यायालय में चल रही कार्यवाही का उपयोग राज्य में हिंसा को और बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकते। अतः न्यायालय उनसे अपील करता है कि वे न्यायालय को ऐसा मंच बनाने का प्रयास न करें जिससे हिंसा और भड़के और वे समस्याएं और मुखर हों जो इस राज्य में पहले से ही चल रही हैं। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ का पूरा ध्यान देश दिल से सम्मान करता है। उन्होंने ये विचार निश्चित रूप से मणिपुर की स्थितियों का अध्ययन करने के बाद पूरे कानूनी नुक्तों का ध्यान रखते हुए ही व्यक्त किये होंगे अतः राजनैतिक दलों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे वोटों का गुणा–गणित छोड़ कर इस राज्य के लोगों के जीवन को शान्तिमय व सुखी बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करें। सवाल यह नहीं है कि राज्य में भाजपा की सरकार है और केन्द्र में भी इसी पार्टी की सरकार है बल्कि सवाल यह है कि भारत के एक सीमान्त राज्य में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और जिस देश में लोग आपस में ही लड़ने लगें वह देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। अतः राष्ट्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि सभी राजनैतिक दल इस राज्य में अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज कर लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाने का पैगाम दें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह देश उन महात्मा गांधी का देश है जो 1947 की आजादी के समय बंगाल में हिन्दू–मुस्लिम फसाद रोकने के लिए अकेले ही इस राज्य में बिना किसी सुरक्षा के एक धोती पहने व हाथ में लाठी लेकर निकल पड़े थे जबकि उस समय पूरे देश में मार–काट का बाजार बहुत गर्म था। पश्चिमी इलाके पंजाब में तो खून की नदियां बह रही थीं। इस क्षेत्र के दंगे रोकने के लिए सेना की सैकड़ों टुकड़ियां तैनात की गई थीं, फिर भी दंगे रुक नहीं रहे थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन ने कहा था कि 'मुझे भारत के पूर्वी क्षेत्र (बंगाल) की चिन्ता नहीं है क्योंकि वहां एक अकेले व्यक्ति की सेना ही दंगा रोकने के लिए काफी है, मुझे असली चिन्ता पश्चिमी क्षेत्र (पंजाब) की है जहां सेना की बटालियन की बटालियनें तैनात हैं'। इसलिए न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ का यह कहना कि यह न्यायालय न तो सुरक्षा प्रणाली चलाता है और न सीधे कानून–व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी को संचालित करता है। अगर वकीलों को यह लगता है कि इस सन्दर्भ में कुछ खामियां या विसंगतियां हैं तो हम सम्बन्धित प्रशासन को नोटिस जरूर जारी कर सकते हैं। अतः इस मामले पर हमें दलगत स्तर से ऊपर उठ कर बहस करनी चाहिए। यह मानवीयता का मामला है। जबकि न्यायालय को यह मालूम है कि संवैधानिक न्यायालय की हैसियत में यह उच्चतम अधिकारों का केन्द्र है। मणिपुर की समस्या को हमें इसी नजरिये से हल करना होगा। अतः इस बारे में जरूर पुनर्विचार करना चाहिए कि हाल ही में तथ्यों की जांच के लिए महिलाओं का जो एक दल गया था उसके तीन सदस्यों के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी गई कि उन्होंने हिंसा को राज्य प्रायोजित कहा था।

आज का राशि फल

मेष :– कुछ अच्छे आसारों से मन प्रफुल्लित रहेगा। पेशे संबंधी कोई यात्रा में अवरोध संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

बृषभ :– स्वयं पर भरोसा रख योजनाओं को सुचारू रुप से क्रियान्वित करें। सगे–संबंधों में सरल व व्यावहारिक बनने की कोशिश करें। अर्थाभाववश चिंता संभव।

मिथुन :– किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध से मन हतोत्साहित होगा। संबंधों के प्रति कुछ नयी शिकायतें संभव। किसी विद्वान के विचारों से प्रभावित मन में उत्साह का संचार होगा।

कर्क :– कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा–प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव।

सिंह :– किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। रोजगार में अति व्यस्तता रहेगी किंतु कायरे को समय से पूर्ण करें।

कन्या :– समस्याओं के समाधान हेतु मन नयी–नयी युक्तियों पर केंद्रित होगा। महत्वपूर्ण कायरें के प्रति आलस्य न करें। छोटी–छोटी बातों पर क्रोधित न हो। जीवन साथी से मधुरता कायम रखें।

तुला :– मन सकारात्मक विचारों से प्रभावित होगा। नाजुक संबंधों में संतुलित वाणी का प्रयोग करें। कोई हितैषी बिगड़े हुए संबंधों को सुधरवायेगा। रोजगार में अपनी क्षमता का लाभ उठाएंगे।

वृश्चिक :– सभी प्रकार के दायित्वों की पूर्ति हेतु संतुलित योजना पर चलें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सगे–संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां संभव।

धनु :– नये समीकरण लाभकारी कार्य क्षमता के परिचायक होंगे। प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आय–व्यय में संतुलन बनाने का प्रयत्न करें। महत्वपूर्ण कायरे में आलस्य का त्याग करें।

मकर :– कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा–प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रोजगार में प्रगति संभव।

कुंभ :– पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर उत्साहित होंगे। नियोजित कार्यकुशलता से प्रगति के लिए आशान्वित होंगे। सुखद कायरें की व्यस्तता रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।

मीन :– क्षमता से परे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना हानिकार हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न करें। रोजगार में लाभ के नये अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा 83 विद्यालयों का किया गया निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कार्यालय महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के पत्र के क्रम मे उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जनपद मे संचालित परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण व संचालित कार्यक्रमों की प्रगति के अनुश्रवण हेतु 13 जुलाई, 2023 को जनपद मे कार्यरत समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक को मिलाकर जनपदीय टास्कफोर्स का गठन कर विकास खण्ड– बरसठी व रामपुर मे अवस्थित उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों मे सघन निरीक्षण अभियान चलाकर शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा– विद्यालय मे शुद्ध पेयजल, कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन, शिक्षकधशिक्षामित्रध अनुदेशक उपस्थिति, छात्र नामांकन, विद्यालय निपुण कार्ययोजना आदि की प्रगति का निरीक्षण किया गया। गठित जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा कुल 83 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमे 01 प्रधानाध्यापक, 04 सहायक अध्यापक, 05 शिक्षामित्र व 03 अनुदेशक अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थित प्रधानाध्यापकध्सहायक अध्यापकधशिक्षामित्रध्अनुदेशक का निरीक्षण तिथि का वेतनध्मानदेय अवरूद्ध करते हुये उक्त के सम्बंध मे अपना स्पष्टीकरण सात दिवस के अन्दर सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किये गये। विद्यालय पर उपस्थित समस्त शिक्षकों को जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर मे वृद्धि लाने, निपुण लक्ष्य प्राप्त करने व विद्यालय प्रांगण की साफ–सफाई एवं विद्यालय मे अध्ययनरत छात्रध्छात्राओं के उपस्थित एवं ठहराव मे वृद्धि करने तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं यथा–यू–डायसध, डी0बी0टी0 आदि को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपदीय टास्क फोर्स के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल द्वारा प्राथमिक विद्यालय बनगाँव पट्टी, वि0क्षे0 बदलापुर के निरीक्षण के दौरान विद्यालय मे कार्यरत समस्त शैक्षणिक कर्मचारी विद्यालय पर उपस्थित पाये गये। विद्यालय में रंगाई–पुताई पायी गयी। विद्यालय प्रांगण साफ–सुथरा पाया गया। विद्यालय मे अध्ययनरत छात्रों को आधुनिक विधा से शिक्षित करने हेतु स्मार्ट कक्षा–कक्ष का उद्घाटन किया गया। विद्यालय के छात्र बहुत ही अनुशासित पाये गये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय मे किये जा रहे नवाचार हेतु प्रधानाध्यापक सहित समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रशंसा करने के साथ–साथ विद्यालय पर उपस्थित समस्त शिक्षकों को छात्रों के अधिगम स्तर मे वृद्धि लाने, निपुण लक्ष्य प्राप्त करने व विद्यालय प्रांगण की साफ–सफाई एवं विद्यालय मे अध्ययनरत छात्रध्छात्राओं के उपस्थिति एवं ठहराव मे वृद्धि करने तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं यथा–यू–डायसध, डी0बी0टी0 आदि को ससमय पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

दिव्यांगजन के सहायतार्थ शासन द्वारा राज्य निधि से चार प्रकार की वित्तीय सहायता किये जाने का प्राविधान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर – जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन के सहायतार्थ शासन द्वारा राज्य निधि से चार प्रकार की वित्तीय सहायता किये जाने का प्राविधान किया गया है। शासन के द्वारा राज्य निधि से चार मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमावली उपलब्ध करायी गयी है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनो द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेलध्ललित कलाध्संगीतध्नृत्यधफिल्मध थियेटरध्साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हो उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने तथा खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियो यथा–कैंसर, थैलिसिमियॉ, प्लास्टिक एनीमियॉ बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हों को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

जनपद के सभी सरकारीध्गैर सरकारी संस्थाएं एवं दिव्यांगजन जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहतें है वे अपने आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में करें। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला दिव्यांगजन सशकतीकरण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न दुनिया भर में एक व्यापक समस्या है चाहे एक विकसित, विकासशील या अविकसित देश हो : प्रशांत कुमार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्एफ.टी.सी.ध्सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशान्त कुमार ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल के निर्देशन में श्यौन उत्पीड़न को अनुचित यौन व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपमानजनक, शर्मनाक या धमकी भरा है पर के विषय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्एफ.टी.सी.ध सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्री प्रशान्त कुमार की देख–रेख में 13 जुलाई 2023 को ''तहसील सभागार केराकत जौनपुर'' में महिलाओं को जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरताध जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्एफ.टी.सी.ध्सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर प्रशान्त कुमार द्वारा बताया गया कि यौन उत्पीड़न को अनुचित यौन व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपमानजनक, शर्मनाक या धमकी भरा है।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न दुनिया भर में एक व्यापक समस्या है चाहे एक विकसित, विकासशील या अविकसित देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दुनिया भर में स्थानिक है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जो पुरूषों और महिलाओं दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। खासकर महिलाओं में यह आम होता जा रहा है। यही कारण है कि उन्हें कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, पीछा करना, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और उनमें से सबसे भयानक अपराध, बलात्कार जैसे अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। इन प्रकरणों से सम्बन्धित महिलाओं को प्राप्त अधिकार व प्राप्त संरक्षण के संबंध में उनको अवगत कराया गया।

तहसीलदार केराकत महेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 भारत में एक विधायी कार्य है जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है साथ ही साथ केन्द्रध्राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। श्रम प्रर्वतन अधिकारी नेहा यादव द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन और उसके जीवन के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को निभाने का अधिकार है किसी भी व्यवसाय, व्यापार पर जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है।

इसी प्रकार श्रम प्रर्वतन अधिकारी द्वारा कारखाना एक्ट व अन्य श्रम कानूनों के तहत प्राप्त संरक्षण और अधिकतम कार्यावधि की अवधि, मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने की व्यवस्था व कार्य स्थल पर शिशुओं को संरक्षित रखने की व्यवस्था व बच्चों को फिडींग करने का अधिकार आदि से अवगत कराया गया साथ में कार्यस्थल पर यदि उनके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न या अन्य किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्थाओं के द्वारा उनको क्या संरक्षण व अधिकार प्रदान किये गये है उनसे अवगत कराकर श्रम से संबंधित विधियों से अवगत कराया गया।

रिटेनर लॉयर देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा बताया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के किसी भी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक अर्थात 15 से 18 तक के किसी भी किशोर को तब तक काम पर नहीं लगाया जा सकता, जब तक डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। कुछ खतरनाक व्यवसायों में बालकों और महिलाओं को लगाना मना है। कारखाना अधिनियम में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की सुविधा का भी वर्णन किया गया है।

इस अवसर पर 60 महिला तथा पी0एल0वी0 गण श्री रविन्द्र कुमार, शिवशंकर सिंह, सुनील कुमार, सुबाष यादव व अन्य ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहें।

पूर्वोत्तर रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रेलमंत्री को संबोधित सुझाव पत्र डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पूर्वोत्तार रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने भारत सरकार के रेल मंत्री को सम्बोधित सुझाव पत्र में गोरखपुर से लखनऊ तथा लखनऊ तक आने–जाने वाली वन्देभारत एक्सप्रेस का संचालन वाया गोण्डा जंक्शन से होकर किये जाने क्योंकि देवीपाटन मण्डल मुख्यालय होने के कारण इसका ठहराव भी गोण्डा जंक्शन पर सुनिश्चित कराये जाने, सरयू साकेत एक्सप्रेस जो मनकापुर से प्रयागराज एवं प्रयागराज से मनकापुर तक आती–जाती है ट्रेन का विस्तार गोण्डा जंक्शन किये जाने जिससे देवीपाटन मण्डल के लाखों यात्री गोण्डा से प्रयागराज तक की यात्रा कर सकें, बहराइच से वाराणसी एवं वाराणसी जंक्शन से बहराइच वाया गोण्डा तक आने जाने वाली इण्टरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव शिवदयालगंज कटरा में करते हुए अविलम्ब संचालन शुरू किये जाने, गोण्डा से कानपुर तक वाया बाराबंकी लखनऊ मेमोध्पैसन्जर ट्रेन का संचालन अविलम्ब शुरू कराये जाने, गोण्डा से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से गोण्डा तक राजधानी या ए0सी0 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किये जाने, 12569ध12570 इण्टरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव इटियाथोक, जरवल रोड एवं बुढ़वल जंक्शन पर किया जाये, गोण्डा कचेहरी रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी के नाम किये जाने, अधिवक्ताओं, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं छात्रध्छात्राओं की सुविधा हेतु बाघ एक्सप्रेस एवं आम्रपाली एक्सप्रेसध्मेल का ठहराव गोण्डा कचेहरी रेलवे स्टेशन पर किया जाये, मैलानी जं0 से लखनऊ जं0 के बीच रेल यात्रियों की सुविधा हेतु इण्टरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कराये जाने, गोण्डा जंक्शन परिसर में रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर अविलम्ब अतिक्रमण हटाने एवं रेलवे आवासों में निवास कर रहे बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाय, गोण्डा जंक्शन पर पुराने माल गोदाम पर चल रहे यात्री प्लेटफार्म का निर्माण शीघ्र पूरा कराये जाने, जिससे गोण्डा लखनऊ तथा लखनऊ गोण्डा तक आवागमन हेतु मेमो ट्रेन का संचालन अविलम्ब शुरू हो सके। मनकापुर जंक्शन स्टेशन पर बाघ, अमरनाथ एवं गोरखधाम एक्सप्रेस का ठहराव किया जाये, लखनऊ मण्डल कार्यालय में 3–3 अपर मण्डल रेल प्रबन्धक पद पर कार्यरत हैं। इनमें से एक अपर मण्डल रेल प्रबन्धक को स्थानान्तरित करके गोण्डा में नियुक्त किये जाने। क्योंकि यहां पहले से ही मण्डल कार्यालय स्थापित करने हेतु, गोण्डा रेलवे चिकित्सालय में डाक्टरों एवं दवाइयों का अभाव है। रेल कर्मचारियों की सुविधा हेतु डाक्टरों की नियुक्ति करते हुए रेल द्वारा निर्धारित अच्छी कम्पनी की दवाईयां उपलब्ध कराये जाने, रेल आवासों की खराब स्थिति के कारण कई घटनाएं घट रही हैं कहीं छत गिर गई है तो कई मकानों पर दीवारों पर दरार आ गयी है। रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्मित लगभग 1700 आवासीय स्थल एवं सड़क स्थानीय निर्माण, इंजीनियरिंग एवं प्रकाश विभाग में कार्यरत उदासीन रेल अधिकारियों एवं वर्षों से तैनात कर्मचारियों की उदासीनता के कारण जर्जर एवं खराब स्थ्झिति में हो गये हैं। इसका पुर्निर्माण कराये जाने, गोण्डा, करनैलगंज, इटियाथोक, बभनान, मसकनवा समेत कई स्थानों पर रेलवे की जमीनों एवं कालोनियों पर बाहरी व्यक्तियों का कब्जा है। कब्जेदारों को हटाकर व्यवसायिक केन्द्र बनाकर सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के आश्रितों को आवंटित किये जाने, करनैलगंज रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक गाड़ी संख्या–11112/1111 सुसाशन एक्सप्रेस का ठहराव किये जाने, पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन की ओर आने जाने वाली सभी जर्जर सड़कों को दुरूस्त किये जाने, गोण्डा जंक्शन रेलवे परिक्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था शून्य है। रेलवे प्रकाश विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी अपने कार्य के प्रति गम्भीर नहीं है। जिससे आमजनमानस को समय–समय पर असुविधा होने के साथ–साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गोण्डा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं0 4, 5 की ओर एक रेल यात्री टिकट सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने का आग्रह किया है।

जेड0आर0यू0सी0सी0 मेम्बर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने विगत दिवस गोरखपुर में रेलवे द्वारा आयोजित हाईस्पीड वन्देभारत एक्सप्रेस शुभारम्भ कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड दिल्ली एवं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सुझाव पत्र दिया गया।

यूपी में मिशन निरामया का शुभारंभ

योगी बोलें, मऊ और शामली माफिया और पलायन के लिए जाना जाता था, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत शामली और मऊ जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए अनुबंध हुआ। वहीं मिशन निरामया के तहत प्रदेश के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग जारी की गई। यही नहीं, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता सुधार के लिए अपनाई गई मेंटॉर–मेंटी प्रक्रिया के तहत 8 नए संस्थानों को मेंटॉर का प्रमाण पत्र दिया गया। 2017 से पहले प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 2017 के बाद पीएम मोदी की एक जिला–एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करते हुए आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। आज 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि 16 जिलों में निर्माणाधीन हैं। मऊ और शामली जैसे जिले, जो आज से 6 वर्ष पहले अन्य कारकों से जाने जाते थे। वहां आज मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे है। मऊ माफिया के कारण भयभीत रहता था, तो शामली में पलायन का दंश था। लेकिन आज इन दोनों ही

जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। यह किसी सपने के साकार होने जैसा है। पिछली सरकारों ने पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थानों को उपेक्षित रखा था। स्टेट मेडिकल फैकल्टी खुद बीमार थी और गुणवत्तापरक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं था। ऐसे में मिशन निरामयाः की आवश्यकता थी। जिसे सरकार ने बढ़ाया। इसके तहत 12 अच्छे संस्थानों को मेंटॉर के रूप में चिह्नित किया गया। मेंटॉर–मेंटी की नीति के साथ आगे बढ़ी सुधार की प्रक्रिया का ही परिणाम है। आज 8 और संस्थान मेंटॉर के रूप में अपग्रेड हो गए हैं। यह बदलती हुई व्यवस्था का प्रमाण है। सीएम योगी ने कहा की शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल, नर्सिंग हो या पैरामेडिकल कॉलेज, अगर गुणवत्ता है, मानक पूरा है तो उसकी शासन की सभी पात्र योजनाओं का लाभ बिना विलंब मिलना चाहिए। अगर वह मानक पूरा नहीं करता तो ऐसे संस्थानों को अपनी सूची से बाहर किया जाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा शुचिता और पारदर्शिता के साथ कि गई नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता रैंकिंग अन्य संस्थानों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) आधार पर मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया था। महाराजगंज और संभल में निजी निवेश कर्ताओं का चयन पूर्व में किया जा चुका है एवं दोनों स्थान पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। आज जनपद मऊ में राजीव सामाजिक शिक्षा सेवा संस्थान को तथा जनपद शामली में चिह्नित प्राईवेट पार्टनर–ज्ञान चेतना एजुकेशलन सोसाइटी एवं उत्तर प्रदेश शासन के बीच एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुआ है। प्रत्येक स्थान पर निजी निवेशकर्ता द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपये के निवेश से एक निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा। मिशन निरामया के तहत नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रयास यह है कि प्रदेश में स्थापित समस्त नर्सिंग व पैरामेडिकल कालेज (सरकारी एवं निजी) का निरीक्षण क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया द्वारा कराया जाये और इसके आधार पर संस्थाओं को एक एक्रीडेशन रैंकिंग स्कोर प्रदान किया जाये। उक्त एक्रीडेशन रैंकिंग एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की गयी है। उत्तर प्रदेश इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी के कायाकल्प की आवश्यकता है। इस दिशा में अच्छे प्रयास भी हुए हैं।

मां की गाली देने पर मौसेरे भाई की हत्या

संवाददाता

लखनऊ। बख्शी का तालाब में मौसेरे भाई ने भाई को लकड़ी के पटरे से पीट–पीटकर हत्या कर दी। दोनों ही शराब के नशे में थे। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां का देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार करने के बाद वह घर पहुंचा तो उसके भाई ने उसे मां की गाली दे दी। इतने में वह गुस्सा हो गया। फिर गाली देने वाले भाई को पीट–पीटकर घायल कर दिया। इसके बाद परिजन घायल को अस्पताल लेकर गए। साढामऊ स्थित रामसागर मिश्र सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का पटरा भी बरामद कर लिया है। मामला थाना क्षेत्र के चंदाकोडर ग्राम पंचायत का मजरा विजयपुर का है। राम प्रसाद गौतम (35) राजगीर (मिस्त्री) का काम करता था। उसी गांव में ही मौसेरा भाई संजय गौतम मजदूरी का काम करता है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह हत्या की सूचना मिली। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। थोड़ी ही देर बाद आरोपी को नन्ना क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अपनी ससुराल बिहार भागने की फिराक में था। आरोपी संजय गौतम ने बताया, सोमवार को उसकी माता सरजू देवी की लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दाह संस्कार के बाद घर पर आए। इसके बाद रात में दारू पीने लगे। उसी दौरान राम प्रसाद ने मां की गाली दे दी। पहले तो उसे मना किया। पर वह मान नहीं रहा था। दोस्ती यारी में गाली दिए जा रहा था। इसके बाद लकड़ी के पटरे से उसे खूब पीटा। वह जब घायल होकर जमीन पर गिर गया तो वहां से भाग गया। मृतक के भाई शिवराज गौतम ने बताया, दोनों भाई छत पर बैठक शराब पी रहे थे। सोमवार रात चीखने की आवाज आई तो जाकर देखा। भाई राम प्रसाद लहुलूहान अवस्था में जमीन पर गिरे थे। आस पास चारों तरफ खून ही खून फैला था। उनके साथ बैठा संजय गौतम मौके से फरार था। भाई को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचे एडीसीपी अभिजीत आर शंकर ने थाना प्रभारी ब्रजेश चंद्र तिवारी को आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मृतक के भाई ने तहरीर दी है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, संजय गौतम ने 2017 में इटौंजा निवासी रिश्ते में भाई लगने वाले की हत्या कर दी थी। इस मामले में वह तीन वर्ष तक जेल में बंद रहा था। संजय को छुड़वाने के लिए मां ने अपनी जमीन तक बेच डाली थी। एक ग्रामीण ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि संजय गौतम ने अपने पिता की कई वर्ष पूर्व हत्या की थी। इस मामले को दबा दिया गया था।

विनाशकाले विपरीत बुद्धि : विशद सागर

संवाददाता

लखनऊ। चारबाग जैन मंदिर में चातुर्मास कर रहे आचार्य गुरुवरश्री विशद सागर ने बुधवार को प्रवचन में कहा कि बुराई में अच्छाई खोजना व अच्छाई को अपनाना, साथ ही बुराई को भूल जाना महानता का लक्षण है। उन्होंने कहा कि पुरुषोतम भगवान राम से हारकर रावण जब मरणासन्न अवस्था में पहुँच गया तब राम ने लक्ष्मण से कहा रावण से हित के वचन ले लो, कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। लक्ष्मण रावण के समीप गये तब रावण जो सूर्व शक्तिमान व ज्ञानवान भी थे। अंत समय मे कहा शक्ति का सदुपयोग व दुरुपयोग दोनो अपने मन पर निर्भर है।

इटावा सफारी में तीन शावकों की मौत दुखद, जिम्मेदारी तत्काल निर्धारित हो : अखिलेश

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इटावा के बीहड़ों में बसे लायन सफारी में एक साथ तीन नवजात शावकों की मौत को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इटावा लॉयन सफारी में 3 शावकों की दुखद मौत की जिम्मेदारी तत्काल निर्धारित हो। अनुभवहीन–अदक्ष नेतृत्व को बदला जाए क्योंकि गर्भवस्था की पूर्वसूचना के बाद भी देखरेख में लापरवाही बरती गयी। न तो प्रक्रिया का पालन किया गया, न आईवीआरआई बरेली व सीजेडए को बताकर पोस्टमार्टम व अंतिम क्रिया हुई। सफारी प्रबंधन तीनों शावक की मौत को छुपाने का प्रयास किया मगर पशुपालन विभाग ने शावकों की मौत की पुष्टि कर दी है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि लायन सफारी में सोना नामक शेरनी ने पांच शावकों को जन्म दिया था लेकिन तीन शावकों की मौत हो गई है। हाल के दिनों में इटावा सफारी में जितने भी शावकों का जन्म हुआ है वो सभी के सभी सुरक्षित हैं अगर ऐसा नहीं होता तो शावकों की संख्या 10 के ऊपर कैसे पहुंच जाती। सफारी के उप निदेशक जयप्रकाश और क्षेत्रीय वन अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव से सफारी में शावक के जन्म लेने और उनकी मौत को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई।

राम नगरी में 45 वर्षीय कांवड़िये की करंट लगने से मौत

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता) राम भक्तिपथ स्थित मार्ग से गुजरने के दौरान वहां खोदे गए डक्ट में भरे पानी में उसका पांव जाने के पश्चात लगा करंट।

बताया यह भी जा रहा है कि अंडरग्राउंड केबल का कोई तार कटा था, जिससे डक्ट में करंट उतर आया था। करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सीओ एसपी गौतम ने श्रद्धालु की मौत की पुष्टि की है।

बेटी को प्रेमी से मोबाइल पर बात करने पर लगाया रोक तो बेटी ने पिता के ही खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

अपने प्रेमी से मोबाइल पर बात करते देख पिता ने बेटी को डांटा और बात करने से रोका तो नाराज बेटी अपने प्रेमी को लेकर पहुंची कोतवाली। काफी मान मनोअल के बाद भी नहीं मानी बेटी, पिता के खिलाफ दर्ज कराया जान से मारने का मुकदमा, पुलिस ने पिता का धारा 151 में किया चालान, दोनो है बालिग, कोतवाली रुदौली के जमुनियामऊ गांव का मामला।

भटपुरा रसूलपुर के प्रधान अनिल गुप्ता को प्रदेश सरकार भेजेगी केरल

उमाकान्त लाला ब्यूरो चीफ

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश से सात अधिकारियों के साथ प्रदेश के 18 प्रधानों को केरल राज्य के लिए भेज रही है स ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि केरल राज्य की ग्राम पंचायतों को देखने और वहा से कुछ नया सीखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश से एक दल को भेज रही है। जिसमें 7 अधिकारियों सहित 18 प्रधान शामिल हो रहे हैं। जिसमें हमारी ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर का भी नाम है। सभी को 16 जुलाई की शाम लखनऊ से फ्लाइट के माध्यम से केरल भेजा जा रहा है। वहां पर हम लोग ग्राम पंचायतों का 6 दिन करने के साथ वहां के प्रधानों से अपनी जानकारी साझा करेंगे। और केरल की ग्राम पंचायतों को देखेंगे व वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे ,और सीख कर फिर अपनी ग्राम पंचायतों में वैसा काम करने की कोशिश भी करेंगे।

व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करें विशेषकर औषधीय पौधे व पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनायें': मनीष सिंह

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एसकेडी एकेडमी के संस्थापक मनीष सिंह ने पौधारोपण अभियान के साथ अपनी सालगिरह के मौके पर वृक्षारोपण को पर्यावरण बचाव की सबसे बड़ी जरुरत बताते हुए अपने सभी छात्रों, अध्यापकों,कर्मचारियों और अतिथिगणों के बीच हजारों की संख्या में पौधों का वितरण कर पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया।

विभिन्न रेजिडेंशियल सोसाइटी में व संस्थानों में भी वृक्षारोपण कराया स वृन्दावन कॉलोनी की एल्डेको सौभाग्यम सोसाइटी में एस के डी ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारी गणों ने निदेशक श्री मनीष सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पूरी सोसाइटी में औषधिय पौधे व कई नीम शीशम आदि वृक्षारोपण किये स

इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि – हमें व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण कर पृथ्वी को प्रदूषणमुक्त करने में अपना भरपूर योगदान देना अति आवश्यक है। इस अवसर पर अपने सारपूर्ण उद्‌बोधन में उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा में नये आयाम प्राप्त करने हैं। उसके लिए हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल देश में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में धार्मिक सौहार्द व सहिष्णुता की विशेष आवश्यकता है। समाज में सब ओर समरसता का वातावरण रहे, आपस में प्रेम बना रहे, इसका प्रयास हर व्यक्ति को करना जरूरी है। उन्होंने संतुलित पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण को सबसे अहम बताया।

गौरतलब है कि मनीष सिंह अपने प्रत्येक जन्मदिन के अवसर पर प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। इस वर्ष भी एस.के.डी. एकेडमी की वृन्दावन शाखा में एस.के.डी. ग्रुप के डायरेक्टर मनीष सिंह ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर वृक्षारोपण को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और अतिथिगणों के मध्य बड़ी संख्या में पौधे वितरित किये। जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने शिक्षकों, कर्मचारियों, बच्चों एवं आये हुए अतिथियों का आभार ज्ञापित किया।

ट्रस्ट के नवनिर्मित भवन में अनुष्ठान का समापन

अयोध्या।(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) श्रीरामजन्मभूमि पर निर्मित हो रहे भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूजन–अर्चन व यज्ञ अनुष्ठान का दौर प्रारंभ हो गया है। इस समय राम मंदिर परिसर के अलावा रामकोट में दो स्थानों पर यज्ञ हो रहा है। ये अनुष्ठान दक्षिण भारत के आचार्यगण संपादित करा रहे हैं। इसी में से रामकोट स्थित ट्रस्ट के नवनिर्मित भवन में चलने वाले अनुष्ठान का समापन बुधवार को हुआ, जिसमें मुख्य यजमान नगर निगम के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय व उनकी पत्नी वंदना उपाध्याय रहीं। इसकी शुरुआत छह जुलाई को हुई |आहुतियां डालने वालों में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र, मंदिर निर्माण से जुड़े प्रचारक गोपाल, विधायक वेद प्रकाश गुप्त प्रमुख रूप से रहे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरित हुआ, यज्ञ लगभग तीन घंटे चला। अनुष्ठान का संयोजन गोकरण वेद विद्यापरिषद कर्नाटक के आचार्यों ने किया।

रानोपाली मे जान जोखिम में मत डालिए जनाब

अयोध्या। (डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) सावधान !, खतरा ! रेलवे क्रासिंग दोनों ओर देखने के बाद ही पार करें! जैसे स्लोगन इन महोदय के लिए बेमानी हो गये हैं। इस युवा को अब कौन बताये कि क्रासिंग बन्द है? मालगाड़ी खड़ी है, लेकिन डिब्बों के बीच नीचे से गुजरना खतरे से खाली नहीं है।यह दृश्य रानोपाली रेलवे क्रासिंग का है।किन्हीं कारणों से क्रासिंग पर ट्रेन खड़ी हुई तो यह युवक नीचे से घुसकर निकलने का प्रयास कर रहा है। यह जल्दबाजी जान पर भारी भी पड़ सकती थी।

वंदे भारत पर पथराव के मामले में अज्ञात पर केस

अयोध्या।(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)। थाना रौनाही क्षेत्र में देवराकोट रेलवे स्टेशन के बीच बंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी में रौनाही थाना व रेलवे पुलिस साक्ष्यों के अभाव में खाली हाथ रही। आरपीएफ के निरीक्षक एसके सिंह की तहरीर पर रेलवे पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।गोरखपुर–अयोध्या से लखनऊ जाने वाली बंदे भारत पर पत्थरबाजी में दो बोगियों के शीशे टूट गए थे। पुलिस ने लखौरी के मजरे बीर भानपुर निवासी नुन्नू पासवान की आधा दर्जन बकरियों के मरने का साक्ष्य बनाते हुए उसे व उसके दो बेटों अजय व विजय को हिरासत में लिया था।एसएसपी राजकरन नैय्यर ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि भी की थी। वहीं, जांच में दोनों बेटों के स्कूल में और पिता नुन्नू पासवान को खेत में होने की पुष्टि हुई। रौनाही पुलिस ने दोनों बेटों को छोड़ दिया था जबकि नुन्नू का शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया।

कांवड़ियों का जत्था बस्ती रवाना, लखनऊ-गोरखपुर हाईवे 16 तक बंद

अयोध्या।रामनगरी के सरयू तट पर बुधवार को कांवड़ियों का बड़ा समागम दिखा। लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे कांवड़िये स्नान के बाद बस्ती भदेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक जल लेकर रवाना हुए। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल कांवड़िये डीजे की धुन पर थिरकते हुए चल रहे हैं। कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ–गोरखपुर हाईवे को 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है।राम नगरी अयोध्या भगवान शिव के जयकारे से गूंज उठी। लाखों की संख्या में पहुंचे कांवड़ियों ने सरयू नदी में स्नान के बाद सरयू तट पर स्थित नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन किए। रामलला के दरबार पहुंचते ही शिव भक्तों ने भगवान श्री राम के जयकारे और बोल बम के नारे भी लगाए। शाम होते ही कांवड़ियों का जत्था बस्ती भदेश्वरनाथ के लिए रवाना होने लगा।इस यात्रा में भगवान शिव की आकर्षक झांकी दिखी तो यात्रा में जल लेकर रवाना हुए कांवड़िये रंगीन लाइटों के बीच डीजे की धुनों पर भगवान शिव के भजनों पर झूमते दिखाई दिए। बता दें कि बुधवार से प्रारम्भ हुई यात्रा 2 दिन के बाद बस्ती पहुंचेगी।15 जुलाई को सावन कृष्ण पक्ष त्र्योदशी को शिवरात्रि के पर्व पर बाबा भदेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया जायेगा।अयोध्या में सरयू तट से निकली कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रही। अयोध्या से बस्ती के बीच शुरू हुई कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए एनएच 27 पर लखनऊ से गोरखपुर नेशनल हाइवे को बंद कर दिया गया है।ड्रोन कैमरे से इस यात्रा की निगरानी की जा रही है। आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया की लाखों की संख्या कांवड़िये आये हैं। सरयू का जल लेकर यात्रा की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर यातायात प्रबंध कर रहे हैं। अयोध्या से बस्ती के बीच पूरी तरह वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है। लखनऊ की तरफ से आने वाले भारी वाहन को रोक दिया गया है।रामनगरी के ऐतिहासिक सावन झूला मेला के बीच कावंड यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिये सबसे बड़ा 132 घंटे का रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए लखनऊ–गोरखपुर हाइवे के बजाय वाहन वैकल्पिक मार्ग से आएंगे और जाएंगे।इस दौरान आकस्मिक वाहन, एंबुलेंस, फायर व अन्य आवश्यक वस्तु के वाहनों को छोड़ गोरखपुर की ओर से आने–जाने वाले वाहनों को कौड़ीराम, बड़हलगंज, दोहरीघाट, जीयनपुर, आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सहजनवा, बस्ती, कलवारी, टांडा से अकबरपुर–दोस्तपुर के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस वे व संतकबीर नगर, बांसी, मेंहदावल,डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, जरवल रोड, चौकाघाट, बदोसराय के रास्ते सफदरगंज,लखनऊ मार्ग पर चलेंगे।कानपुर की तरफ से आने वाले वाहन उन्नाव, रायबरेली, बछरावा, हैदरगढ़ व फतेहपुर, डलमऊ, रायबरेली के जगदीशपुर से,आगरा एक्सप्रेस वे से आने वाले वाहन मोहान, जुनाबगंज, मोहनलालगंज, गोसाईगंज के रास्ते,सीतापुर–शाहजहाँपुर से आने वाले वाहन आईआईएम रोड दुबग्गा से आलमबाग, नहरिया से शहीदपथ होते हुए अहीमामऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते गोरखपुर जाएंगे। बलरामपुर, श्रावस्ती से लखनऊ जाने वाले वाहन गोंडा, कर्नलगंज से जरवल रोड वाया चौकाघाट,बदोसराय, सफदरगंज और बहराइच से आने वाले वाहन वाया कर्नलगंज, जरवल रोड, चौकाघाट, बदोसराय, सफदरगंज से लखनऊ आएंगे और जाएंगे।

प्राथमिक शिक्षा की आधुनिकतम तकनीक लाया, विद्यालय संस्कारों की पाठशाला : राकेश त्रिपाठी

संवाददाता

लखनऊ। कानपुर रोड स्थित मानसरोवर योजना में द विद्यालय संस्कारों की पाठशाला प्ले ग्रुप स्कूल्स की चेन का उद्घाटन चेयरमैन हैदरगढ़ आलोक तिवारी, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी तथा सुरेश चन्द्र तिवारी पूर्व एमडी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग ने किया।

इस मौके पर 11 शाखाओं का उद्घाटन वर्चुअल मोड में किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शिक्षाविद अजय दुबे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि द विद्यालय नामचीन किड्स एजुकेशन संस्थानों को कड़ी चुनौती देगा क्योंकि यहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी आदान–प्रदान होगा। पिछले 15 वर्षों से लाखों नौजवानों को रोजगार की राह दिखा चुके बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक, शिक्षाविद अजय दुबे ने अब बचपन को भी संस्कारित करते हुए शिक्षित करने की ठान ली है। विद्यालय संस्कारों की पाठशाला के नाम से प्ले ग्रुप स्कूल्स चेन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ साथ पौराणिक शिक्षा पद्धति पर बच्चों को शुरू से ही संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाएगा। विद्यालय में डे केयर, प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी कक्षाओं में आधुनिकतम तकनीक से लैस स्मार्ट क्लासेज होंगी तथा बालिकाओं का प्रवेश शुल्क शून्य रखा गया है।

विद्यालय प्ले ग्रुप स्कूल्स चेन की शुरुआत करने की आवश्यकता का जवाब देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय दुबे ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर केवल अक्षरों का ज्ञान या रटंत विद्या ही सम्पूर्ण शिक्षा नहीं है इसका अनुभव मैंने बड़े विद्यार्थियों को शिक्षित करते हुए किया। बचपन से बच्चों में आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों का प्रवाह हो जो राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हो इसी मूल भावना से विद्यालय कार्य करेगा। द विद्यालय के लोगो में दिख रही पांच कमल की पंखुड़ियां पंचतत्वों का प्रतीक है जो शैशवास्था और बाल्यावस्था को संस्कारों से पल्लवित पुष्पित करेगा।

आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए श्री दुबे ने बताया कि 11 जुलाई को द विद्यालय की 11 शाखाओं का एक साथ उद्घाटन किया जाएगा।

कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही के दिए गए विभागीय अधिकारियों को निर्देश

संवाददाता

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति अवगत कराया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल की अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 16 जून को बैठक हुई थी। बैठक में व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुख सचिव शनमुगा सुंदरम, परिवहन विभाग के प्रबंध संचालक आरके उपाध्याय, विशेष सचिव राजस्व राम रतन, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग विभाग के उप सचिव सुभाष बाबू, खाद्य रसद विभाग के विशेष सचिव अतुल सिंह, अपर आयुक्त अटल कुमार राय, के अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, उपाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, सचिव अरुणा शुक्ला, महेंद्र सिंह एवं नितिन गोस्वामी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग ने 16 जून 2023 को संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी कर दिया है, संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में विभाग ने अवगत कराया था कि एएनएम के पद भरे गए हैं तथा अन्य संवर्गों के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने हेतु ई अधियाचन एवं पदोन्नत के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं, मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक कीटसंग्रह कर्ता, सहित विभिन्न वर्गों की लंबित वेतन विसंगतियों पर निर्णय कराए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2023 को संपन्न हुई बैठक के निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, नगरीय परिवहन सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों संविदा राशि के मामले में एकरूपता लाए जाने तथा उनका समायोजन नगरीय परिवहन सेवाओं में किए जाने के संबंध में मुख सचिव के निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उनकी सेवा एवं वेतन का संरक्षण किए जाने के संबंध में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग ने अवगत कराया कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जाएस नई पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों को वित्त विभाग को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, एनपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 50: पेंशन का निर्धारण किए जाने के संबंध में बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने पर वित्त विभाग ,को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश कार्यवृत्त के माध्यम से जारी किए गए हैं, चकबंदी अधिकारी के पदों को राजपत्रित घोषित किए जाने के संबंध में कार्मिक एवं राजस्व विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं स कार्य देशक के 33: पदों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था से अलग किए जाने एवं पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने के संबंध में बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा को तत्काल कार्यवाही कराए जाने के के लिए कहा गया है।

लखनऊ में बनेगा कैंसर रिसर्च सेंटर

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में कैंसर का विश्वस्तरीय क्लीनिकल ट्रायल व रिसर्च तथा डेवलपमेंट सेंटर बनेगा।यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके निर्माण के लिए आगे आई है। सेंटर के निर्माण पर 820 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंपनी ने चकगंजरिया सिटी में कैंसर संस्थान के पास पांच एकड़ और 2500 वर्ग मीटर जमीन अलग से क्लीनिकल ट्रायल के लिए मांगी गई है। इन्वेस्ट यूपी ने एलडीए उपाध्यक्ष को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।आने वाले वर्षों में लखनऊ में कैंसर की दवाएं बनेंगी, क्लीनिकल ट्रायल होगा।यह देश का इकलौता सेंटर होगा।यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी कार्प डाइम लिमिटेड निर्माण करेगी। अधिकारियों के मुताबिक चक गंजरिया में पहले से ही कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है। इस केंद्र के निर्माण सेकैंसर संस्थान को मदद मिलेगी।

औद्योगिक भूखंडों की आज ई-नीलामी करेगी प्रदेश सरकार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 13 जुलाई को औद्योगिक भूखंडों की 'ई–नीलामी' करेगी। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस कदम के तहत लखनऊ, कानपुर, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी और अलीगढ़ में औद्योगिक भूखंडों की नीलामी होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा ने इस नीलामी की तैयारी की है। इसके तहत 154 औद्योगिक भूखंडों, तीन समूह आवासीय भूखंडों, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, आठ वेयरहाउस के लिए भूखंडों की नीलामी की जाएगी।

मिशन 2024: उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का प्लान तैयार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 2024 को लेकर तैयारी जबरदस्त कर रही है। बीजेपी का फोकस विपक्षी वोटों में सेंधमारी कर ज्यादा है।एनडीए के खाते में अधिकाधिक सीटे लाना है। विपक्ष के वोटों पर नजरें गड़ाए बीजेपी का लक्ष्य तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर है। विपक्षी दलों के नाखुश नेताओं और पुराने साथी रहे सुभासपा लीडर ओमप्रकाश राजभर से जिस तरह इधर वार्ता और मेलमिलाप का सिलसिला चल रहा है, उससे साफ नजर आने लगा है कि अब एनडीए के हिस्सा बने या तब बने। समाजवादी पार्टी के खास मित्र जयंत चौधरी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। रालोद यदि एनडीए में आ जाये तो जाट प्रभावित सीटे जुड़ सकती हैं। अब जयंत चौधरी पर निर्भर करेगा कि वे विपक्ष में रहकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे या बीजेपी के साथ। पश्चिम में जयन्त चौधरी की पार्टी का करीब एक दर्जन सीटों पर प्रभाव है। महंगाई, बेरोजगारी और कृषि विपक्ष के मुख्य मुद्दे हैं। यह बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं इसलिए सतर्क हो गई है। बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के जरिये हर लोकसभा सीट की पोजीशन जांची है। इसी के मार्फत अपने सांसद और विधायकों की कूबत और आमजन के बीच लोकप्रियता का जायजा लिया है। बीजेपी का थिंकटैंक कभी खाली नहीं बैठता है। कभी बैठक तो कभी प्रबुद्ध सम्मेलन या फिर कोई अन्य कार्यक्रमों के सहारे जनता के बीच सरकार और बीजेपी की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करते रहते हैं। इसी दौरान सम्भावित सरकारों को भांपने का भी काम करते हैं। कार्यकर्ताओं और भावी प्रत्याशियों की स्वीकार्यता को भी देख लेते हैं। परफार्मेंस ठीक नहीं तो पार्टी हाईकमान टिकट काटने में तनिक देर नहीं करेगा। उसका लक्ष्य सीट जीत का है। छोटे–छोटे दलों को पार्टी से जोड़कर बीजेपी ताकत बढ़ाने में लगी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद आरएसएस ने मुखपत्र 'द ऑर्गनाइजर में बीजेपी सलाह दी थी कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं। क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी कार्यशैली की जरूरत है। बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान में सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर कार्यक्रमो के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश की। ओबीसी और दलितों का दिल जीतने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पसमांदा मुस्लिम को भी टारगेट किया है। पसमांदा मुसलमानो के बीच पार्टी जनों को लगाया गया है।

कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने का दिखावा करती है बीजेपी : मनजीत

संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिन्दुओं की ठेकेदार होने का दावा करती है। कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने का दिखावा करते हैं परन्तु कांवड़ यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाओं की भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की। इस बार मानसून जल्दी आ जाने से कांवड़यात्रियों को परेशानी हो रही है उनकी रात में ठहरने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। पेयजल व शौचालय तक की व्यवस्था रास्तों पर नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए हिन्दुओं का वोट तो हासिल कर लिया लेकिन उनकी भावनाओं से खेल रही है। सरकार ने मंदिर मस्जिद, श्मशान कब्रिस्तान, गाय गोबर के नाम पर सिर्फ लोगों को लड़ाने का किया है। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कांवड़ यात्रियों को सुविधा देने की बजाय उनका सहारा लेकर धार्मिक उन्माद भड़काने का काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली से प्रतीत होता है कि शासन एवं प्रशासन धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में पूरी तरह से अक्षम है।

बारिश और बाढ़ से प्रदेश के दर्जनों जिले तबाह : रालोद

संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि यूपी के दो दर्जन से अधिक जनपदों में बारिश व बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बड़े पैमाने पर जान माल व पशु धन की हानि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मकान गिर गये हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी हैं। ऐसे में विकट हालात में भी सरकार अपने आंख कान बंद किये है। पीड़ितो की ईमानदारी के साथ मदद नहीं हो रही है। श्री दुबे मुख्यमंत्री से बाढ़ प्रभावित जनपदों में युद्धस्तर पर मदद करने की मांग की है। श्री दुबे ने कहा कि बारिश से बाढ़ आई है और किसानों का खासा नुकसान हुआ है और नुकसान हो सकता है। प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिससे गांव के गांव उजड़ गये है तथा किसानों की लहलहाती फसल बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो रही है लेकिन प्रशासन मूक बाधिर बना तमाशा देख रहा हैं। उन्होंने कहा कि सूखे की मार का दंश झेल रहा किसान अभी उससे उबर ही नही पाया था कि बाढ़ के प्रकोप ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है जिससे उसकी कमर टूट गयी है। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, आजमगढ़, संतकबीरनगर, देवरिया, शाहजहांपुर, अयोध्या, मऊ अम्बेडकरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर में बाढ़ का प्रकोप है और प्रदेश सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं। बस्ती, संतकबीर नगर तथा देवरिया जनपद में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जिससे दर्जनों गांवों में पानी घुसने से लोग पलायन कर रहे हैं इसी तरह बहराइच के आधा दर्जन गांव कटान के निशान पर हैं दर्जनों मकान और सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा गई, कई जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। पश्चिमी उत्तर के मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में भारी बारिश होने का येलो एलर्ट जारी किया गया है। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। शामली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी के चलते सहपत में तटबंध टूट गया है। कैराना यमुना ब्रिज पर जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बिजनौर, हापुड़ और सहारनपुर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं लेकिन सरकारी मशीनरी राहत एवं बचाव कार्य के नाम पर हीलाहवाली कर रही है। श्री दुबे ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को युद्धस्तर पर जमीनी राहत पहुंचाने के कड़े निर्देश जारी करे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराने हेतु बाढ़ प्रभावित जिलों में एक बाढ़ कंट्रोल रूम के तहत विशेष अधिकारियों की एक टीम गठित कराये जिससे लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने में सहायता मिल सके।

हिन्दी सान्ध्य दैनिक देश की उपासना

स्वत्वाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास्तव की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI सन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।